THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMAIAH). (a) Yes, Sir.

(b) Applications pending for allotment are as under:—

Type	*No of applications*
I	4,255
II	10,073
III	1,515
IV	868
V	593
VI	250
VII	278
VIII	79
Hostel	423
TOTAL	18,334

SHRI K. SURYANARAYANA. May I know whether the Government has any plans to overcome all these things because the Government is also paying heavy rent to the higher officers? Will the Government solve all the accommodation problem or at least type IV, V and VI before the end of the Fifth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI H. K. L. BHAGHAT). It will not be posible to make available accommodation to all those who are eligible for allotment by the end of the Third Fove Year Plan The Ministry had asked for Rs. 150 crores for that purpose. In that case 75 per cent people could have been accommodated But Rs. 100 crores was allocated and out of that during the three years much less money was given. Therefore, it will not be possible to accommodate them before the end of the Fifth Plan.

SHRI K SURYANARAYANA: How many officers have vacated Government accommodation and have gone back to their own houses?

SHRI H. K. L. BHAGAT: On account of the new policy of the Government, the total number was 4161 and out of them 1665 have vacated. I have a list of different categories and if the hon. Member desires, I can supply that to him.

SHRI D. N. TIWARY. May I know whether the Government has made any special provision for those Government servants who are ailing or whose family members are ailing? Whether they will be given preference in allotment of quarters or they will have to go by turn?

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: There is preference in allotment of quarters to Government servants on grounds of health. Certain types of diseases have been recognised A Committee has been appointed where all these applications ares considered before such an allotment is made.

SHRI R S PANDEY While appreciating the efforts made by Mr Bhaghat and Mr. Raghu Ramaiah in providing accommodation to Government servants as early as possible—they deserve congratulations for that—may I know how many applications are pending with you for allotment of accommodation?

SHRI H. K. L BHAGAT· I have already given figures in the original reply. The total number of pending applications is 18334. Now, I may add for the information of the Hon. Member that so far the satisfaction average is 42 4 per cent out of the total who are entitled to it. I have with me the details regarding various categories and if he wants I can give him the details.

Plan for Pest Control

*187. SHRI HARI SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state·

(a) whether Government have recently, formulated an integrated plan

for pest control involving students and farmers on mass scale; and

(b) if so, broad features of the plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) Yes, Sir. The Indian Council of Agricultural Research has prepared an integrated plan for this purpose.

(b) A national plan for rodent control and management has been prepared involving agencies like the ICAR, CSIR, Universities, Voluntary organisations and various Central and State Departments for successfully implementing different aspects of the plan. This national plan includes training of personnel at various levels, preparation of the rural community plan through extention agencies like All India Radio, T. V. (SITE) and newspapers, involvement of the students for the control of rodents, white-grubs and weeds. A National Coordination Committee has been proposed to ensure the effective implementation of the Plan

श्री हरी सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि पेस्ट कंट्रोल के सिलसिले में जिन विश्वविद्यालयों को लिखा गया है, उनका क्या रेस्पांस है, वे प्रत्येक कालेज से कितने विद्यार्थियों को इस स्कीम के मातहत काम में लगाना चाहते है और उन विद्यार्थियों को इस काम में लगाने की प्रैक्टिकल शेप क्या होगी ।

श्री शाहनवाज खां : अभी यह सारी स्कीम जेरे-गौर है ।

श्री हरी सिंह : इस प्रश्न की महत्ता के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में फसल के एक भारी हिस्से को विभिन्न प्रकार के कीडे खा रहे हैं । होता यह है कि अगर एक किसान अपने खेत में कीड़ों को मारने में समर्थ हो जाता है, लेकिन अगर उसके पडौसी किसान अपने खेतों में पेस्ट कंट्रोल नहीं करते है, तो इस सम्बन्ध में किया गया सारा प्रयत्न इनइफेक्टिव हो जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने एक्सटेंसिव पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या स्कीम बनाई है, जिसके द्वारा हिन्दुस्तान की कुछ स्टेट्स में पेस्ट कंट्रोल कर गया जाये ।

श्री शाहनवाज खां : हुकूमत ने पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत सी स्कीम्ज बनाई है । पेस्ट कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके है । एक तो बायालोजिकल कंट्रोल है । एक किस्म के कीडे फसल को नुकसान पहुंचाते है । उन कीडों को जो कीडे मारते हैं, उनको प्रीडेटर कहा जाता है । हम इस तरफ भी काम कर रहे है । जहां हम देखते है कि बडे स्केल पर पेस्ट्स का एटैक हो गया है, वहां हम ग्राउण्ड स्प्रेइंग भी करते हैं और एयरियल स्प्रेइंग भी करते है ।

श्री राजदेव सिंह : गवर्नमेंट का एक आर्गेनाइजेशन है पेस्टीसाइड्ज एसोसियेशन आफ इंडिया । उसके एक एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मि० बरुआ ने यह स्टेटमेंट दिया था कि इस देश की जितनी आबादी है, उससे सात गुना चूहे इस देश में है । थोडे दिन पहले मैट्रल फूड एडवाइजरी कमेटी के सामने यह सजेशन आया था कि गवर्नमेंट रेडियो, टेलीविजन और पेम्फलेट्स के द्वारा यह प्रचार कराये कि जो व्यक्ति एक चूहे को मारेगा, उसको आठ आने या एक रुपया पुरस्कार दिया जायेगा । हम समझते है कि इस तरह पूरे देश में चूहे मारे जा सकते हैं । मै यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या पेस्ट और चूहे एक ही हैं ?

श्री शाहनवाज खां : रोडेंट्स भी इसमें शामिल हैं ।

उस मीटिंग में इस मसले पर बातचीत हुई थी। रोडेन्ट कंट्रोल के लिए हुकूमत कदम उठा रही है। उसके मातहत हम खाने की चीज के साथ जहर मिलाकर और ट्रेप लगा कर रोडेन्ट्स को मारते है। इसके लिए कई तरीके है। चूहों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है।

श्रीमती शीला कौल : क्या यह सच है कि चूहे एक दिन में एक आदमी का खाना खा लेते है? पेस्ट कंट्रोल की प्लान के मातहत जो काम किया जा रहा है, उसमे बहुत ढील हो जाती है। उदाहरण के लिए गेहूं के बीज बोये जाते है और चूहे उनको खा लेते है, लेकिन पेस्ट कंट्रोल की मेडिसन्ज बाद मे बांटी जाती हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कदम उठा रही है?

श्री शाहनवाज खां : यह सही है कि चूहे बहुत बड़ी मिकदार मे अनाज खा जाते है। कितने चूहे एक आदमी का खाना खा सकते है, यह बात इस पर भी मुनहसिर है कि कोई आदमी कितना खाना खाता है।

श्री शिवनाथ सिंह : हमारी प्रोडक्शन को बढाने के लिए पेस्ट कंट्रोल बहुत आवश्यक है। हमने जितनी भी रस्ट-प्रूफ वैरायटीज निकाली है, वे टोटल फेल्योर साबित हुई है। मैं यह जानना चाहता हू कि गवर्नमेंट एक सही रास्ट प्रूफ वैरायटी तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है। हमारे देश के कई क्षेत्रों में रस्ट एपिडेमिक के रूप मे फैल रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है?

श्री शाहनवाज खां : हमारे जितने रिसर्च इंस्टाट्यूट्स हैं, खास तौर से आई० ए० आर० आई०, वे हर वक्त रस्ट-रेसिस्टेंट वैरायटीज की खोज मे मसरूफ है। माननीय सदस्य को यह जान कर खुशी होगी कि हमने ऐसी वैरायटीज निकाली हैं, जो रस्ट-रेसिस्टेंट है। अगर माननीय सदस्य मुनासिब समझे, तो मैं उनको पूसा ले चलूंगा और उन को कुछ वैरायटीज दिखाऊंगा।

Sugarcane Arrears

+

*188. SHRI SARJOO PANDEY:

SHRI P. M. MEHTA:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Sugar Mills in different States owe huge amounts to the cane-growers;

(b) if so, the quantum of such dues in each of the sugarcane producing State, separately, and

(c) how do Government propose to help the growers to realise their dues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN). (a) and (b) A statement showing State-wise the arrears of cane price relating to 1975-76 and earlier seasons as on 15-2 1976 is placed on the Table of the Sabha Placed in Library. See No LT-10489/76.

(c) The State Governments have been advised from time to time to ensure prompt payment of cane dues by factories, take stringent measures against defaulting factories including their prosecution, make provisions in their enactments for payment of interest at 12 per cent and take steps for recovery of the arrears of sugarcane prices as arrears of land revenue. Some State Governments have already taken steps to increase the rate of interest to 15 per cent and have provided for recovery of arrears of cane price as arrears of land revenue. Legal action has also been taken in a few cases where there was delay in the payment of arrears.